However, the demands for introduction of a direct train between Delhi and Kotdwara have been examined more than once but not found feasible of implementation immediately due to resource & operational constraints including saturated terminals in Delhi area.

Establishment of South Western Railway Zone in Hubli

642. SHRI K. RAHMAN KHAN : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether Government have taken a decision to establish South Western Railway Zone in Hubli in Karnataka;

(b) if so, by when the Zone is likely to function; and

(c) if answer to part (a) is in the negative whether such a proposal is before the Government and if so, by when a decision would be taken?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY RAILWAYS (SHRI SATPAL MAHARAJ): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The Government has decided to create additional Railway Zonal offices with Headquarters at Jaipur, Allahabad, Bangalore, Hajipur, Jabalpur and Bhubaneswar.

Flaws in Education System

643. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA : Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the newsitem, captioned "Flaws in education system discovered", as reported in the Hindustan Times, dated the 8th June, 1996;

(b) if so, whether the education system in the country has been found inadequate;

(c) if so, whether Government propose to bring amendments to the education policy to make it effective and job-oriented; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPTT. OF EDUCATION IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI MUHI RAM SAIKIA) : (a) Yes, Sir.

(b) The Report refers mainly to the issues like drop-out rates resources and quality only.

(c) and (d) The National Policy on Education (NPE), 1986 and its Programme of Action (POA) were up-dated and placed before the Parliament in 1992. As of now, the emphasis would be on toning up implementation and stepping up resources for education so that there is a better linkage between education and the world of work and improvement of access, retention and quality at all states of education, particularly elementary education.

कुलियों द्वारा अनारक्षित डिब्बों पर कब्जा किया जाना

644. **श्री रामदेव भंडारी:**
श्री ईश दत्त यादव:
श्री नागमणि:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 3 जुलाई, 1996 के नवभारत टाइम्स के दिल्ली संस्करण में "अनारक्षित डिब्बों पर कब्जा कर सीटें बेचने वाले गिरोह सक्रिय" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, बल्कि देश के पटना, हावड़ा जैसे कई महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर अनारक्षित डिब्बों की सीटों पर कब्जा कर बेचने वाला गिरोह सक्रिय है जिसमें पुलिस, रेल कार्मिक तथा कुली शामिल हैं; यदि हां तो, किन-किन रेलवे स्टेशनों के संबंध में इस प्रकार की शिकायतें मिली हैं और ऐसी शिकायतों की संख्या कितनी है; और

(ग) सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) जी हां.

(ख) पिछले एक वर्ष में, मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, मुंबई सैन्ट्रल, बांद्रा टर्मिनल, हावड़ा, दिल्ली जंक्शन, मद्रास सैन्ट्रल और मद्रास एग्मोर स्टेशनों के संबंध में कुल 13 शिकायतें प्राप्त हुई थी। इसके अलावा, आयोजित की गई निवारक जांचों के दौरान, लाइसेंसधारी भारिकों और समाज-विरोधी तत्वों द्वारा अनारक्षित सवारी डिब्बों में सीटें घेरने की घटनाएं दादर टर्मिनस, पुणे, न्यू जलपाईगुड़ी और कुर्ला टर्मिनस पर पकड़ में आई।

(ग) गाड़ियों में स्थान घेरने की घटनाएं रोकने के लिए उठाए गए विभिन्न कदम इस प्रकार हैं:-

(घ) ऐसी गतिविधि की आशंका वाली गाड़ियों के अनारक्षित सवारी डिब्बे प्लेटफार्म पर विधिवत रूप से मार्ग-रक्षण के अधीन और तालाबंद करके लाए जाते हैं।

(ii) प्रारंभिक स्टेशनों पर अनारक्षित यात्रियों का प्रवेश पंक्ति लगवाकर नियमित किया जाता है।

(iii) समय-समय पर लाइसेंसधारी भारिकों और अन्य समाजविरोधी तत्वों के विरुद्ध निवारक जांच की जाती हैं। नियम विरुद्ध गतिविधियों में लिप्त पाए जाने वाले लाइसेंसधारी भारिकों के लाइसेंस बैज निलंबित/समाप्त कर दिए जाते हैं। ऐसी गतिविधियों में लिप्त पाए गए अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध रेल अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में महिला छात्रावासों का निर्माण

†645. **श्री अजीत जोगी:**
श्री एस॰ एस॰ सुरजेवाला:

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश के ग्रामीण क्षेत्रों में राज्यवार और वर्षवार कितने महिला छात्रावास निर्मित किए गए;

(ख) इन ग्रामीण महिलाओं को उनसे क्या-क्या लाभ मिल रहे हैं;

(ग) क्या सरकार वर्ष 1996-97 के दौरान देश के ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे और छात्रवासों के निर्माण की मंजूरी देने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ कितना धन आवंटित किया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस॰ आर॰ बोम्मई): (क) ग्रामीण क्षेत्रों में स्वीकृत होस्टलों की संख्या विवरण में दी गई है (नीचे देखिये)।

(ख) ये परियोजनाएं होस्टल वाले शहरों में रोजगार-रत महिलाओं को चाहे वे देश के किसी भी हिस्से से आयी हो, उपयुक्त, सुरक्षित और सस्ता होस्टल आवास उपलब्ध कराने के लिए हैं।

(ग) और (घ) स्वीकृति पात्र संगठनों से स्कीम की पद्धति के अनुसार पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने पर निर्भर करती है। प्रत्येक राज्य के लिए अलग से लक्ष्य और राशि निर्धारित नहीं की जाती।

विवरण

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वीकृत कामकाजी महिला होस्टल

क्रम संख्या	राज्य का नाम	स्वीकृत होस्टलों की संख्या 1993-94	1994-95	1995-96
1.	आन्ध्र प्रदेश	-	1	-
2.	कर्नाटक	-	2	-
3.	केरल	1	2	4
4.	मध्य प्रदेश	1	-	-
5.	महाराष्ट्र	3	3	-
6.	मिजोरम	-	-	1
7.	उडीसा	-	1	-
8.	तमिलनाडु	-	13	4
9.	उत्तर प्रदेश	1	1	-
10.	पश्चिम बंगाल	-	-	1
	योग:	6	23	10

Technical assistance by UNDP

646. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether UNDP gives technical assistance to the Government on project/programme basis in the agricultural sector;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) how many UNDP assisted projects/programmes are currently being implemented in the State of Madhya Pradesh with details thereof?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI CHATURANAN MISHRA): (a) and (b) Yes, Sir. The United Nations Development Programme (UNDP) gives technical assistance by supplying materials and equipment, training provide services of experts/consultants Organising of national and international workshops, fellowships, etc, through projects programmes in various fields of agriculture.

(c) the Following two UNDP assisted projects are being implemented in Madhya Pradesh, in addition to other States:

(i) Development and Strengthening of Integrated Pest Management (IPM) in India; and

(ii) Development of Oilseeds and Pulses Programme.